

मुख्य समाचार:-

- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए निर्देश।
- नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत प्रदेश के अठहत्तर नगरीय निकायों में स्वीकृत आकांक्षी शौचालयों के निर्माण की समय-सीमा निर्धारित की।
- उपमुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि बिलासा देवी कंवट विमानतल के रनवे विस्तार का कार्य तेज गति से किया जाएगा।
- बस्तर जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत-चार अन्य घायल।

प्रगति-पचासवीं बैठक

सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र "प्रगति" ने अपनी पचासवीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पंद्रह में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों का भी माध्यम साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने "प्रगति" की पचासवीं बैठक को प्रदेश के लिए दूरगामी महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि इससे भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और रायगढ़ स्थित लारा सुपर थर्मल पावर जैसी परियोजनाओं को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षमता, निवेश और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रगति प्लेटफॉर्म ने वास्तविक अर्थों में शासन का समाधान उन्मुख मॉडल प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री-भर्ती परीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं और परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। श्री साय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई और चयन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं, पीएससी की परीक्षा प्रणाली को और अधिक समकालीन, पारदर्शी तथा अभ्यर्थी हितैषी बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई।

शौचालय निर्माण-समय/सीमा

नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत प्रदेश के अठहत्तर नगरीय निकायों में स्वीकृत एक सौ इकतालीस आकांक्षी शौचालयों का निर्माण पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत रूफ स्तर के निर्माण वाले शौचालयों को इकतीस जनवरी और लिंटल स्तर के शौचालयों को अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। वहीं, जिन शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, उन्हें भी इकतीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य शासन ने नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं के साथ ही नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय अवधि में शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं होने पर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड—दो हजार पच्चीस के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक मीडिया संस्थान कल सात जनवरी तक अपनी प्रविष्टियां नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रविष्टियां ई-मेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती हैं। राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड के तहत चार श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया –टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया – रेडियो तथा ऑनलाइन-इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल हैं। चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आगामी पच्चीस जनवरी को सम्मानित किया जाएगा।

स्त्री परियोजना

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग—डीएसआईआर ने धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान—एनआईटी रायपुर को “स्त्री परियोजना” की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत तीन साल के लिए नब्बे लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से तीन सौ ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास और समावेशी प्रगति की दृष्टि के अनुरूप है। उन्होंने इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में तीन सौ ग्रामीण महिलाओं को कोसा रेशम फाइबर निष्कर्षण, आधुनिक बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

टंकराम वर्मा—प्रेसवार्ता

राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने आज अपने विभागों के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री वर्मा ने बताया कि एग्रीस्टेक के तहत जिओ रिफ्रेंसिंग, फार्मर रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है। साथ ही नक्शे के जियो रिफ्रेंसिंग के लिए पच्चीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी भू-नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक भूखंड में यूनिक आइडेंटिटी पिन देते हुए जमीनों का भू-आधार कार्ड जारी किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा जल्द हो सके, इसलिए जमीन के सभी दस्तावेज को सिविल न्यायालय से डिजिटलाइज करते हुए जोड़ दिया गया है। श्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार ने दो वर्षों में अनेक कार्य किए हैं। वहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

बिलासपुर विमानतल

उपमुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा है कि बिलासपुर स्थित चकरभाठा के बिलासा देवी कॅवट विमानतल के रनवे विस्तार का कार्य तेज गति से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रनवे के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित दो सौ नब्बे एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए पचास करोड़ रुपये का मुआवजा जमा कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एयरपोर्ट के विस्तार से बिलासपुर संभाग में निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्रवासियों को हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा।

धान खरीदी केन्द्र—अनियमितता

जशपुर जिले के कोनपारा धान खरीदी उप केंद्र में छह करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से फड़ प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी ने धान खरीदी उप केंद्र में छह करोड़ पचपन लाख रुपये से अधिक की राशि की अनियमितता की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

सरगुजा ठंड-स्कूल बंद

उत्तरी छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके मद्देनजर सरगुजा जिले में कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और अन्य स्कूल दस जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सभी शिक्षक और अन्य स्टाफ निर्धारित समय में स्कूल में उपस्थित रहेंगे। हालांकि, उन सभी को भी ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दुर्घटना

बस्तर जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को दरभा के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि एक पिकअप वाहन में सवार होकर कुछ लोग पखनार के साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। इसी दौरान दरभा थाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-तीस पर एक ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

माओवादी-आत्मसमर्पण

धमतरी जिले में आज पांच लाख रुपये की एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस माओवादी ने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडेय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह माओवादी नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में लंबे समय से सक्रिय थी। आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

संक्षिप्त समाचार

— केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। यह सेवा तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। गौरतलब है कि सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष सत्रह फरवरी से शुरू होंगी।

— रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आठ जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

